

Practice Paper 1: Criminal Law & Constitution

अभ्यास प्रश्नपत्र 1: आपराधिक विधि और संविधान

20

Questions • प्रश्न

24

Minutes • मिनट

20

Marks • अंक

EN•हि

Bilingual • द्विभाषी

Instructions • निर्देश

- Each question has four options; choose the one best answer.
प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं; एक सर्वोत्तम उत्तर चुनें।
- Time the paper strictly. Negative marking varies by state (none, $\frac{1}{4}$ or $\frac{1}{3}$); follow your state's pattern.
समय का कड़ाई से पालन करें। नकारात्मक अंकन राज्यवार भिन्न है (नहीं, $\frac{1}{4}$ या $\frac{1}{3}$); अपने राज्य के पैटर्न का पालन करें।
- Attempt the full paper before opening the answer key and explanations at the end.
अंत में दी गई उत्तर कुंजी और व्याख्या देखने से पहले पूरा प्रश्नपत्र हल करें।
- Laws cited follow BNS, BNSS and BSA (in force from 1 July 2024) where relevant.
जहाँ प्रासंगिक है, BNS, BNSS और BSA (1 जुलाई 2024 से प्रभावी) के अनुसार।
- Take this paper online with timer, instant score and subject-wise analysis: scan the QR code on any page.
टाइमर, तुरंत स्कोर और विषयवार विश्लेषण के साथ ऑनलाइन टेस्ट दें: किसी भी पृष्ठ का QR कोड स्कैन करें।

Subjects in this paper • विषय

BNS	6	BSA	3
BNSS	4	Constitution	7

Original practice paper by Nyaya Pathshala faculty • not a previous-year paper



Questions • प्रश्न

1. The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 came into force on:

BNS

भारतीय न्याय संहिता, 2023 कब लागू हुई?

(A) 1 January 2024

1 जनवरी 2024

(B) 1 April 2024

1 अप्रैल 2024

(C) 1 July 2024

1 जुलाई 2024

(D) 26 January 2025

26 जनवरी 2025

2. How many sections does the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 contain?

BNS

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में कितनी धाराएँ हैं?

(A) 511

511

(B) 358

358

(C) 531

531

(D) 170

170

3. Which new form of punishment has been introduced by Section 4(f) of the BNS?

BNS

BNS की धारा 4(f) द्वारा कौन-सा नया दंड जोड़ा गया है?

(A) Forfeiture of property

संपत्ति की ज़बती

(B) Community service

सामुदायिक सेवा

(C) Solitary confinement

एकांत कारावास

(D) Transportation for life

आजीवन निर्वासन

4. "Snatching" has been made a distinct offence under which section of the BNS?

BNS

BNS की किस धारा में "छीना-झपटी" (snatching) को अलग अपराध बनाया गया है?

(A) Section 303

धारा 303

(B) Section 304

धारा 304

(C) Section 309

धारा 309

(D) Section 316

धारा 316

5. Murder by a group of five or more persons on grounds such as race, caste, sex or language (mob lynching) is punishable under:

BNS

पाँच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा जाति, नस्ल, लिंग या भाषा जैसे आधार पर हत्या (मॉब लिंगिंग) किस धारा में दंडनीय है?

(A) Section 101 BNS

धारा 101 BNS

(B) Section 103(1) BNS

धारा 103(1) BNS

(C) Section 103(2) BNS

धारा 103(2) BNS

(D) Section 105 BNS

धारा 105 BNS



6. "Organised crime" is defined and punished under which section of the BNS?

BNS

"संगठित अपराध" BNS की किस धारा में परिभाषित और दंडित है?

(A) Section 111
धारा 111

(B) Section 113
धारा 113

(C) Section 147
धारा 147

(D) Section 152
धारा 152

7. A "Zero FIR", registered irrespective of the area where the offence was committed, is provided for in:

BNS

"ज़ीरो एफ़आईआर", जो अपराध के क्षेत्र की परवाह किए बिना दर्ज होती है, का प्रावधान कहाँ है?

(A) Section 154 BNSS
धारा 154 BNSS

(B) Section 173 BNSS
धारा 173 BNSS

(C) Section 175 BNSS
धारा 175 BNSS

(D) Section 180 BNSS
धारा 180 BNSS

8. Under Section 187(3) BNSS, default bail becomes available if the chargesheet is not filed within 90 days in cases punishable with:

BNSS

धारा 187(3) BNSS के तहत 90 दिन में आरोप-पत्र न आने पर डिफ़ॉल्ट ज़मानत किन मामलों में मिलती है?

(A) Imprisonment up to 3 years
3 वर्ष तक के कारावास वाले

(B) Imprisonment up to 7 years
7 वर्ष तक के कारावास वाले

(C) Death, life imprisonment or imprisonment of 10 years or more
मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या अधिक के कारावास वाले

(D) Fine only
केवल जुर्माने वाले

9. Trial in absentia of a proclaimed offender who has absconded is provided for in:

BNSS

फ़रार उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में मुक़दमे (trial in absentia) का प्रावधान कहाँ है?

(A) Section 84 BNSS
धारा 84 BNSS

(B) Section 299 BNSS
धारा 299 BNSS

(C) Section 356 BNSS
धारा 356 BNSS

(D) Section 482 BNSS
धारा 482 BNSS

10. Under Section 193 BNSS, the investigation into an offence of rape must be completed within:

BNSS

धारा 193 BNSS के तहत बलात्कार के अपराध की जाँच कितने समय में पूरी होनी चाहिए?

(A) One month
एक महीना

(B) Two months
दो महीने

(C) Three months
तीन महीने

(D) Six months
छह महीने

11. The certificate required for admitting an electronic record in evidence is now provided under:

BSA

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य में स्वीकार करने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र अब किस धारा में है?

(A) Section 61 BSA
धारा 61 BSA

(B) Section 63 BSA
धारा 63 BSA

(C) Section 65B BSA
धारा 65B BSA

(D) Section 85 BSA
धारा 85 BSA



12. A confession made to a police officer is inadmissible against the accused under:

BSA

पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध किस धारा के तहत अग्राह्य है?

(A) Section 22 BSA
धारा 22 BSA

(B) Section 23 BSA
धारा 23 BSA

(C) Section 26 BSA
धारा 26 BSA

(D) Section 39 BSA
धारा 39 BSA

13. The statement of a person as to the cause of his death (dying declaration) is relevant under:

BSA

किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण के बारे में उसका कथन (मृत्युकालिक कथन) किस धारा में सुसंगत है?

(A) Section 26(a) BSA
धारा 26(a) BSA

(B) Section 32(1) BSA
धारा 32(1) BSA

(C) Section 27 BSA
धारा 27 BSA

(D) Section 57 BSA
धारा 57 BSA

14. The right to free and compulsory education (Article 21A) was inserted by the:

Constitution

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A) किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

(A) 42nd Amendment, 1976
42वाँ संशोधन, 1976

(B) 44th Amendment, 1978
44वाँ संशोधन, 1978

(C) 86th Amendment, 2002
86वाँ संशोधन, 2002

(D) 93rd Amendment, 2005
93वाँ संशोधन, 2005

15. The "basic structure" doctrine was laid down in:

Constitution

"मूल ढाँचा" (basic structure) का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ?

(A) Golak Nath v. State of Punjab (1967)
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

(B) Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

(C) Minerva Mills v. Union of India (1980)
मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)

(D) Maneka Gandhi v. Union of India (1978)
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)

16. Which writ is issued to quash an order of an inferior court or tribunal passed without jurisdiction?

Constitution

किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के क्षेत्राधिकार के बिना पारित आदेश को रद्द करने के लिए कौन-सी रिट जारी होती है?

(A) Mandamus
परमादेश

(B) Quo warranto
अधिकार-पृच्छा

(C) Certiorari
उत्प्रेषण (सर्टिओरारी)

(D) Habeas corpus
बंदी प्रत्यक्षीकरण

17. Dr. B.R. Ambedkar called which Article the "very soul" and "heart" of the Constitution?

Constitution

डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा?

(A) Article 14
अनुच्छेद 14

(B) Article 19
अनुच्छेद 19

(C) Article 21
अनुच्छेद 21

(D) Article 32
अनुच्छेद 32



18. A Judge of a High Court holds office until the age of:

Constitution

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर रहते हैं?

(A) 60 years
60 वर्ष

(B) 62 years
62 वर्ष

(C) 65 years
65 वर्ष

(D) 70 years
70 वर्ष

19. "Procedure established by law" must be just, fair and reasonable, held the Supreme Court in:

Constitution

"विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त होनी चाहिए, यह किस मामले में कहा गया?

(A) A.K. Gopalan v. State of Madras (1950)
ए.के.गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)

(B) Maneka Gandhi v. Union of India (1978)
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)

(C) ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976)
एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976)

(D) Kharak Singh v. State of U.P. (1962)
खड़क सिंह बनाम उ.प्र. राज्य (1962)

20. The right to privacy was declared a fundamental right by a nine-judge bench in:

Constitution

निजता के अधिकार को नौ न्यायाधीशों की पीठ ने किस मामले में मौलिक अधिकार घोषित किया?

(A) K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)
केएस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)

(B) Navtej Singh Johar v. Union of India (2018)
नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)

(C) Shreya Singhal v. Union of India (2015)
श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)

(D) Joseph Shine v. Union of India (2018)
जोसेफ़ शाइन बनाम भारत संघ (2018)

NYAYA PATHSHALA



Answer key • उत्तर कुंजी

1 C	2 B	3 B	4 B	5 C	6 A	7 B	8 C	9 C	10 B
11 B	12 B	13 A	14 C	15 B	16 C	17 D	18 B	19 B	20 A

Explanations • व्याख्या

1. (C) 1 July 2024 — The BNS, BNSS and BSA all came into force on 1 July 2024, replacing the IPC, CrPC and the Indian Evidence Act.

(C) 1 जुलाई 2024 — BNS, BNSS और BSA तीनों 1 जुलाई 2024 से लागू हुए और इन्होंने IPC, CrPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया।

2. (B) 358 — BNS has 358 sections (the IPC had 511). BNSS has 531 and BSA has 170.

(B) 358 — BNS में 358 धाराएँ हैं (IPC में 511 थीं)। BNSS में 531 और BSA में 170 धाराएँ हैं।

3. (B) Community service — Section 4 BNS lists the punishments; clause (f) adds community service, for petty offences such as certain cases of theft and defamation.

(B) सामुदायिक सेवा — धारा 4 BNS में दंडों की सूची है; खंड (f) सामुदायिक सेवा जोड़ता है, जो चोरी और मानहानि के कुछ छोटे मामलों जैसे अपराधों के लिए है।

4. (B) Section 304 — Section 304 BNS defines and punishes snatching. Theft is Section 303, robbery Section 309 and criminal breach of trust Section 316.

(B) धारा 304 — धारा 304 BNS छीना-झपटी को परिभाषित और दंडित करती है। चोरी धारा 303, लूट धारा 309 और आपराधिक न्यासभंग धारा 316 में है।

5. (C) Section 103(2) BNS — Section 103(2) BNS specifically covers murder by a group of five or more acting in concert on such grounds, punishable with death or life imprisonment.

(C) धारा 103(2) BNS — धारा 103(2) BNS विशेष रूप से ऐसे आधारों पर पाँच या अधिक लोगों के समूह द्वारा मिलकर की गई हत्या को दंडित करती है; सज़ा मृत्युदंड या आजीवन कारावास है।

6. (A) Section 111 — Section 111 BNS deals with organised crime. Section 113 covers terrorist acts and Section 152 acts endangering the sovereignty, unity and integrity of India.

(A) धारा 111 — धारा 111 BNS संगठित अपराध से संबंधित है। धारा 113 आतंकवादी कृत्य और धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है।

7. (B) Section 173 BNSS — Section 173 BNSS (old Section 154 CrPC) requires information of a cognizable offence to be recorded irrespective of the area, and allows information by electronic communication.

(B) धारा 173 BNSS — धारा 173 BNSS (पुरानी धारा 154 CrPC) के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना क्षेत्र की परवाह किए बिना दर्ज होगी, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना भी दी जा सकती है।

8. (C) Death, life imprisonment or imprisonment of 10 years or more — The 90-day limit applies to offences punishable with death, life imprisonment or imprisonment of ten years or more; for other offences the limit is 60 days.

(C) मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या अधिक के कारावास वाले — 90 दिन की सीमा मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दस वर्ष या अधिक के कारावास वाले अपराधों पर लागू होती है; बाक़ी अपराधों में सीमा 60 दिन है।

9. (C) Section 356 BNSS — Section 356 BNSS is a new provision allowing inquiry, trial and judgment in the absence of a proclaimed offender, subject to safeguards.

(C) धारा 356 BNSS — धारा 356 BNSS एक नया प्रावधान है जो कुछ सुरक्षा उपायों के साथ उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जाँच, मुकदमा और निर्णय की अनुमति देता है।



10. (B) Two months — Investigation of rape (and specified POCSO offences) must be completed within two months from the date the information was recorded.

(B) दो महीने — बलात्कार (और निर्दिष्ट पॉक्सो अपराधों) की जांच सूचना दर्ज होने की तारीख से दो महीने में पूरी होनी चाहिए।

11. (B) Section 63 BSA — Section 63 BSA replaces Section 65B of the Evidence Act. The certificate is now in a prescribed form in the Schedule, with a part to be filled by an expert.

(B) धारा 63 BSA — धारा 63 BSA ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का स्थान लिया है। प्रमाणपत्र अब अनुसूची में निर्धारित प्रारूप में है, जिसका एक भाग विशेषज्ञ भरता है।

12. (B) Section 23 BSA — Section 23 BSA combines old Sections 25 and 26 of the Evidence Act: confessions to police, or in police custody unless before a magistrate, cannot be proved against the accused.

(B) धारा 23 BSA — धारा 23 BSA ने साक्ष्य अधिनियम की पुरानी धारा 25 और 26 को मिलाया है: पुलिस के समक्ष, या मजिस्ट्रेट के सामने न होने पर पुलिस हिरासत में की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती।

13. (A) Section 26(a) BSA — Old Section 32(1) of the Evidence Act is now Section 26(a) of the BSA.

(A) धारा 26(a) BSA — साक्ष्य अधिनियम की पुरानी धारा 32(1) अब BSA की धारा 26(a) है।

14. (C) 86th Amendment, 2002 — The Constitution (86th Amendment) Act, 2002 inserted Article 21A for children aged 6 to 14, and also Article 51A(k).

(C) 86वाँ संशोधन, 2002 — संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21A और साथ ही अनुच्छेद 51A(k) जोड़ा।

15. (B) Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) — A 13-judge bench in Kesavananda Bharati held that Parliament can amend the Constitution but cannot destroy its basic structure. Minerva Mills later applied the doctrine.

(B) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) — केशवानंद भारती में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, पर उसके मूल ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकती। बाद में मिनर्वा मिल्स में इस सिद्धांत को लागू किया गया।

16. (C) Certiorari — Certiorari quashes a decision already made without or in excess of jurisdiction. Prohibition is issued to stop proceedings while they are still pending.

(C) उत्प्रेषण (सर्टिओरारी) — उत्प्रेषण (certiorari) क्षेत्राधिकार के बिना या उससे बाहर लिए गए निर्णय को रद्द करती है। प्रतिषेध (prohibition) तब जारी होती है जब कार्यवाही लंबित हो और उसे रोकना हो।

17. (D) Article 32 — Article 32, the right to move the Supreme Court for enforcement of fundamental rights, was described by Ambedkar in the Constituent Assembly as the heart and soul of the Constitution.

(D) अनुच्छेद 32 — अनुच्छेद 32, यानी मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, को आंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का हृदय और आत्मा कहा था।

18. (B) 62 years — Under Article 217(1), High Court judges hold office until 62. Supreme Court judges retire at 65 under Article 124(2).

(B) 62 वर्ष — अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक पद पर रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनुच्छेद 124(2) के तहत 65 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं।

19. (B) Maneka Gandhi v. Union of India (1978) — Maneka Gandhi read Articles 14, 19 and 21 together and held that any procedure depriving liberty must be fair, just and reasonable, departing from the narrow view in A.K. Gopalan.

(B) मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) — मेनका गांधी मामले में अनुच्छेद 14, 19 और 21 को साथ पढ़ा गया और कहा गया कि स्वतंत्रता छीनने वाली प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए; यह ए.के.गोपालन के संकीर्ण दृष्टिकोण से अलग था।

20. (A) K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) — In K.S. Puttaswamy (2017), a nine-judge bench unanimously held privacy to be intrinsic to Article 21 and the freedoms in Part III.

(A) केएस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) — केएस. पुट्टस्वामी (2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि निजता अनुच्छेद 21 और भाग III की स्वतंत्रताओं का अभिन्न अंग है।

